

# डॉ मनमोहन सिंह एवं नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की आर्थिक व विदेश नीति का तुलनात्मक अध्ययन

डॉ राकेश कुमार जायसवाल

असिस्टेंट प्रोफेसर/विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान

राजकीय महाविद्यालय, बदायूँ (उत्तर प्रदेश)

## सारांश

इस उद्देश्य में भारत के डॉ. मनमोहन सिंह और नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत की विदेश नीतियां दो अलग-अलग दृष्टिकोणों को प्रतिबिंबित करती हैं जो उनकी नेतृत्व शैली और बदलते भू-राजनीतिक परिवेश के अनुरूप हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (2014-2024) और मनमोहन सिंह (2009-2014) के नेतृत्व में भारत के आर्थिक प्रदर्शन की तुलनात्मक जांच करना है, जो 2009 से 2024 तक के आर्थिक संकेतकों की एक विस्तृत श्रृंखला पर ध्यान केंद्रित करता है। प्राथमिक उद्देश्य विसंगतियों की पहचान करने और आर्थिक नीति प्रभावी रूप से किस हद तक संचालित होती है, इसकी अंतर्दृष्टि देने के लिए वास्तविक समय के आर्थिक संकेतकों की तुलना में जीडीपी विकास संख्या की निर्भरता का मूल्यांकन करना है। दोनों शासनों के दौरान अर्थव्यवस्था की स्थिति का निर्धारण करने के उद्देश्य से, ऑटोमोबाइल की घरेलू बिक्री, खुदरा ऋण, एयरलाइन यातायात, बुनियादी ढाँचा विकास, कर राजस्व और मुद्रास्फीति दर जैसे प्रमुख संकेतकों का मूल्यांकन किया जाता है। इस तथ्य के बावजूद कि मोदी के कार्यकाल के दौरान रिपोर्ट की गई जीडीपी वृद्धि अधिक थी, परिणाम बताते हैं कि कई वास्तविक समय के संकेतक सिंह की सरकार के दौरान बेहतर प्रदर्शन करते थे

**खोजशब्द :** आर्थिक संकेतक, भारत, आर्थिक नीतियां, विदेश नीति, डॉ. मनमोहन सिंह, नरेन्द्र मोदी

## परिचय

पिछले दशक में, भारत की आर्थिक प्रगति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मनमोहन सिंह के नेतृत्व में विपरीत नीतियों और प्रदर्शन द्वारा चिह्नित की गई है। इस अवधि में आर्थिक नीतियों, विनियामक ढाँचों और वैश्विक आर्थिक प्रभावों में महत्वपूर्ण बदलाव देखे गए, जिनमें से सभी ने भारत की विकास कहानी को आकार दिया है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का 2009 से 2014 तक का कार्यकाल आर्थिक उदारीकरण, समावेशी विकास पहल और बुनियादी ढाँचे और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों में पर्याप्त सार्वजनिक निवेश पर जोर देने वाली नीतियों द्वारा चिह्नित किया गया था। इन नीतियों का उद्देश्य 2008 के वित्तीय संकट के बाद वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना था।

इसके विपरीत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में अपने "मोदीनॉमिक्स" एजेंडे के माध्यम से अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के वादों के साथ पदभार संभाला, जिसमें राजकोषीय अनुशासन, संरचनात्मक सुधार और मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी पहलों पर जोर दिया गया। मोदी के कार्यकाल में व्यापार करने में आसानी बढ़ाने, विदेशी निवेश

आकर्षित करने और स्वच्छ भारत और आयुष्मान भारत जैसी पहलों के माध्यम से सतत विकास को बढ़ावा देने की मांग की गई। इन प्रशासनों के तहत आर्थिक प्रदर्शन को समझने के लिए रिपोर्ट किए गए जीडीपी विकास के आंकड़े केंद्रीय हैं, जो उनकी स्थिरता और सटीकता के लिए जांच के दायरे में आ गए हैं, विशेष रूप से 2015 में जीडीपी गणना में पद्धतिगत परिवर्तनों के बाद। मोदी के कार्यकाल के दौरान उच्च जीडीपी विकास दर की रिपोर्ट के बावजूद, इन आंकड़ों के वास्तविक समय के आर्थिक संकेतकों के साथ संरेखण के बारे में सवाल बने हुए हैं जो जमीनी स्तर की आर्थिक गतिविधियों और भावनाओं को दर्शाते हैं। यह पत्र मनमोहन सिंह के तहत 2009-2014 और नरेंद्र मोदी के तहत 2014-2024 की अवधि में प्रमुख आर्थिक संकेतकों का व्यापक तुलनात्मक विश्लेषण करता है। वाहनों की घरेलू बिक्री, खुदरा ऋण, औद्योगिक उत्पादन, कर संग्रह, बुनियादी ढांचे के विकास और अन्य जैसे संकेतकों की जांच करके, इस अध्ययन का उद्देश्य इन अवधि के दौरान व्यवसायों और व्यक्तियों द्वारा अनुभव की गई आर्थिक वास्तविकताओं की अंतर्दृष्टि प्रदान करना है।

## अध्ययन का उद्देश्य

1. प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और मनमोहन सिंह के प्रशासन के तहत चयनित संकेतकों के प्रदर्शन का मूल्यांकन और तुलना करना।
2. भारत में नीति-निर्माण और आर्थिक विश्लेषण के प्रभाव की जांच करना।

## क्रियाविधि

यह अध्ययन आर्थिक प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए प्रमुख आर्थिक संकेतकों का तुलनात्मक विश्लेषण करता है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी (2014-2024) और मनमोहन सिंह (2009- 2014) के प्रशासन के तहत भारत। कार्यप्रणाली में पंद्रह महत्वपूर्ण आर्थिक संकेतकों का चयन करना शामिल है जो आर्थिक गतिविधि और प्रदर्शन के विभिन्न पहलुओं को पकड़ते हैं। इन संकेतकों में दोपहिया वाहनों, कारों, ट्रैक्टरों और वाणिज्यिक वाहनों के घरेलू बिक्री के आंकड़े, वृद्धिशील खुदरा ऋण, एयरलाइन यात्री यातायात, भारतीय रेलवे यात्री राजस्व, सीमेंट और स्टील के उत्पादन और खपत के स्तर, आयकर और निगम कर संग्रह में वृद्धि दर, पेट्रोलियम उत्पादों की खपत पैटर्न, मुद्रास्फीति दर, घरेलू वित्तीय बचत और सड़क निर्माण से संबंधित मीट्रिक शामिल हैं।

## डेटा विश्लेषण

इस अध्ययन का डेटा विश्लेषण प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह (2009-2014) और नरेंद्र मोदी (2014-2024) के कार्यकाल के दौरान प्रमुख आर्थिक संकेतकों का तुलनात्मक विश्लेषण प्रदान करता है। विश्लेषण में भारत की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं की जांच की गई है, जिसमें घरेलू वाहन बिक्री, कृषि और औद्योगिक संकेतक, वित्तीय संकेतक, बुनियादी ढांचा और ऊर्जा, और परिवहन और औद्योगिक उत्पादन शामिल हैं। प्रत्येक श्रेणी दो प्रशासनों के तहत आर्थिक प्रदर्शन में अंतर को उजागर करती है।

### तालिका 1. वाहनों की घरेलू बिक्री

संकेतक	सिंह का कार्यकाल (2009-2014)	मोदी का कार्यकाल (2014-2024)
--------	------------------------------	------------------------------

मोटरसाइकिल बिक्री वृद्धि(%)	12.44	5.35
स्कूटर बिक्री वृद्धि (%)	25.7	13.21
कार बिक्री वृद्धि (%)	7.92	4.42

व्याख्या: भारत में मोटरसाइकिल और स्कूटर की बिक्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 2009 से 2014 के बीच क्रमशः 12.44 प्रतिशत और 25.7% बढ़ी। ये आंकड़े मजबूत उपभोक्ता विश्वास और मजबूत शहरी और ग्रामीण आर्थिक गतिविधि दिखाते हैं। इस दौरान मोटरसाइकिल और स्कूटर की बिक्री में तेज़ी से वृद्धि हुई, जिसने उपभोक्ता की क्रय शक्ति और आर्थिक जुड़ाव को प्रदर्शित किया। 2014 से 2024 तक, नरेन्द्र मोदी की सरकार ने मोटरसाइकिल और स्कूटर की बिक्री की वृद्धि को 5.35% और 13.21% तक धीमा कर दिया। मोदी के कार्यकाल में आर्थिक अनिश्चितता और बदलते बाज़ार की गतिशीलता के कारण उपभोक्ता तेज़ी से सतर्क हो रहे हैं। उच्च मूल्य की खरीद को प्रभावित करने वाले व्यापक आर्थिक मुद्दों के कारण कार की बिक्री में गिरावट आई है,

### तालिका 2. कृषि और औद्योगिक संकेतक

संकेतक	सिंह का कार्यकाल (2009-2014)	मोदी का कार्यकाल (2014-2024)
ट्रैक्टर बिक्री वृद्धि (%)	15.73	4.49
वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री वृद्धि )%(	10.5	9.74
सीमेंट उत्पादन वृद्धि (%)	7.05	4.32
इस्पात खपत वृद्धि (%)	7.18	5.18

व्याख्या: 2009 से 2014 तक मनमोहन सिंह के कार्यकाल में ट्रैक्टर की बिक्री में सालाना 15.73 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो कृषि में तेज़ी और किसानों के लिए अच्छी परिस्थितियों को दर्शाता है। इस विस्तार ने ग्रामीण आर्थिक जीवंतता और कृषि की सफलता को दिखाया। 2014 से 2024 तक, नरेन्द्र मोदी के तहत ट्रैक्टर की बिक्री में वृद्धि घटकर 4.49% हो गई। मोदी के तहत कृषि क्षेत्र की समस्याओं और ग्रामीण मांग में मंदी ने कृषि विकास और किसान आय वृद्धि को धीमा कर दिया है। दोनों प्रशासनों ने वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री में मजबूत वृद्धि देखी, जो औद्योगिक गतिविधि और बुनियादी ढाँचे के विकास को दर्शाता है। हालांकि, मोदी के तहत विकास दर सिंह के तहत 10.50% से गिरकर 9.74% हो गई। निर्माण और बुनियादी ढाँचा सीमेंट उत्पादन मोदी के तहत 4.32% बढ़ा, जबकि सिंह के तहत 7.05% बढ़ा इन व्याख्याओं से पता चलता है कि किस प्रकार आर्थिक नीतियां जांचे गए समय में कृषि समृद्धि, औद्योगिक प्रगति और बुनियादी ढाँचे के विकास को अत्यधिक प्रभावित कर सकती हैं।

### तालिका 3. वित्तीय संकेतक

संकेतक	सिंह का कार्यकाल (2009-2014)	मोदी का कार्यकाल (2014-2024)
वृद्धिशील खुदरा ऋण वृद्धि (%)	22.47	19.92
आयकर वृद्धि (%)	17.53	16.85
निगम कर वृद्धि (%)	13.09	11.2
घरेलू वित्तीय बचत वृद्धि (%)	13	11.94

व्याख्या: मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी के तहत वित्तीय आंकड़ों की तुलना मामूली अंतर के साथ एक स्थिर विकास ट्रैक दिखाती है। 2009 से 2014 तक सिंह के नेतृत्व के दौरान खुदरा ऋण 22.47% वार्षिक रूप से चढ़े, जो उच्च उपभोक्ता विश्वास और व्यय को दर्शाता है। 2014 से 2024 तक मोदी की सरकार के दौरान खुदरा ऋण वृद्धि 19.92% तक गिर गई, लेकिन लगातार बढ़ी, जो उपभोक्ता मांग और आर्थिक गतिविधि को दर्शाती है। दोनों शासनों ने आयकर राजस्व में वृद्धि की, जिसमें सिंह की 17.53% वृद्धि हुई जबकि मोदी की 16.85%। यह परिवर्तन आर्थिक परिवर्तनों के कारण है जो लाभप्रदता और आर्थिक लचीलापन बनाए रखते हुए कंपनी की प्रतिस्पर्धात्मकता और अनुपालन को बढ़ावा देते हैं। सिंह के कार्यकाल में घरेलू वित्तीय बचत में 13.00% वार्षिक वृद्धि देखी गई देखे गए उतार-चढ़ाव दर्शाते हैं कि नीतिगत कार्य और आर्थिक परिस्थितियां किस प्रकार महत्वपूर्ण वित्तीय संकेतकों को प्रभावित करती हैं, जिसने पिछले दशक के दौरान भारत की आर्थिक प्रगति को प्रभावित किया है।

#### तालिका 4. बुनियादी ढांचा और ऊर्जा

संकेतक	सिंह का कार्यकाल (2009-2014)	मोदी का कार्यकाल (2014-2024)
सड़क निर्माण वृद्धि (%)	5.29	8.25
पेट्रोलियम उत्पादों की खपत वृद्धि (%)	3.47	5.91

व्याख्या: 2009 से 2014 तक, मनमोहन सिंह के कार्यकाल में सड़क निर्माण में सालाना 5.29% की वृद्धि हुई, जो बुनियादी ढांचे में प्रगति को दर्शाता है। हालांकि, 2014 से 2024 तक नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में सड़क विकास की वृद्धि दर सालाना 8.25% तक बढ़ गई। यह उछाल आर्थिक विकास और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए भारत के सड़क नेटवर्क को विकसित और आधुनिक बनाने के मोदी के लक्ष्य का समर्थन करता है। सिंह ने 2009 से 2014 तक पेट्रोलियम उत्पाद की खपत में सालाना 3.47% की वृद्धि का नेतृत्व किया, जो निरंतर उद्योग और परिवहन आवश्यकताओं का संकेत देता है। मोदी के 2014-2024 प्रशासन ने सिंह की तुलना में बुनियादी ढांचे के विकास और आर्थिक विकास, कनेक्टिविटी और औद्योगिक उत्पादन में सुधार के लिए एक आक्रामक दृष्टिकोण अपनाया।

#### डॉ. मनमोहन सिंह का कार्यकाल (2004-2014)

डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति व्यावहारिक थी और आर्थिक कूटनीति पर केंद्रित थी। उनकी सरकार ने भारत को विश्वव्यापी शक्ति बनाने के लिए 1990 के दशक के आर्थिक परिवर्तनों पर निर्माण करके वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया। सिंह ने भारत के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दीर्घकालिक स्थिरता, बहुपक्षवाद और सॉफ्ट पावर पर जोर दिया।

#### सिंह की विदेश नीति के मुख्य पहलू:

**अमेरिका-भारत संबंधों को मजबूत करना:** 2008 के अमेरिका-भारत असैन्य परमाणु समझौते ने भारत-अमेरिका संबंधों को बदल दिया और भारत के परमाणु बाजार के अलगाव को समाप्त कर दिया। इस समझौते ने भारत को एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति बना दिया और इसकी ऊर्जा आवश्यकताओं को सुरक्षित किया।

**बहुपक्षीय कूटनीति पर ध्यान:** सिंह ने बहुपक्षवाद को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स और सार्क में भारत की स्थिति को मजबूत किया। उनके प्रशासन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बदलावों को बढ़ावा दिया और भारत को वैश्विक दक्षिण प्रतिनिधि के रूप में शामिल किया।

**एशिया के साथ आर्थिक एकीकरण:** सिंह की "लुक ईस्ट पॉलिसी" ने दक्षिण पूर्व एशिया के साथ आर्थिक एकीकरण पर जोर दिया, विशेष रूप से आसियान के माध्यम से। इस दृष्टिकोण ने वाणिज्य को बढ़ाया और अन्य देशों के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत किया।

**चीन और पाकिस्तान के साथ संबंधों को संतुलित करना:** सिंह ने सीमा संघर्ष और सुरक्षा समस्याओं के बावजूद चीन और पाकिस्तान के साथ संबंध विकसित करने की कोशिश की। सिंह ने कश्मीर सहित नियंत्रण रेखा को स्थिर करने के लिए पाकिस्तान के साथ बातचीत जारी रखी। संघर्षों के बावजूद सिंह ने टकराव के बजाय जुड़ाव का पक्ष लिया।

**सॉफ्ट पावर का लाभ उठाना:** सिंह ने सांस्कृतिक कूटनीति के माध्यम से अपने विश्वव्यापी प्रभाव का विस्तार करने के लिए भारत के प्रवासी, संस्कृति और लोकतंत्र का उपयोग किया।

भारत सरकार ने अफ्रीका, मध्य पूर्व और अमेरिका में भारतीय प्रवासियों के बीच सद्भावना और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा दिया। सिंह ने अपने पूरे कार्यकाल में आर्थिक प्रगति और भारत की छवि को एक स्थिर, गैर-खतरनाक विकासशील शक्ति के रूप में बढ़ावा दिया। उनकी पहल ने भारत की विदेश नीति को आकार देने के लिए आर्थिक समृद्धि को कूटनीतिक जुड़ाव के साथ जोड़ा।

## नरेंद्र मोदी का कार्यकाल (2014-2024)

नरेंद्र मोदी की मजबूत विदेश नीति आर्थिक लक्ष्यों को रणनीतिक और सुरक्षा संबंधी विचारों के साथ जोड़ती है। मोदी को "मजबूत कूटनीति" कहा जाता है, जो भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा और क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा में भागीदारी बढ़ाने पर केंद्रित है। मोदी के प्रशासन ने सिंह की परियोजनाओं को बनाए रखा है और नई परियोजनाओं को जोड़ा है।

## मोदी की विदेश नीति के प्रमुख पहलू:

**इंडो-पैसिफिक साझेदारी को मजबूत करना:** मोदी की "एक्ट ईस्ट पॉलिसी", सिंह की लुक ईस्ट पॉलिसी का परिणाम है, जिसमें इंडो-पैसिफिक में गहन जुड़ाव की मांग की गई है। भारत ने इंडो-पैसिफिक में चीन के प्रभाव का मुकाबला करने और "स्वतंत्र और खुले" क्षेत्र को सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता (क्वाड) में अपनी भागीदारी बढ़ाई।

**रणनीतिक रक्षा गठबंधनों को मजबूत करना:** मोदी ने अमेरिका, फ्रांस, इजरायल और जापान के साथ सैन्य संबंधों को मजबूत किया है। "मेक इन इंडिया" के माध्यम से, मोदी की सरकार ने अंतरराष्ट्रीय रक्षा आयात पर निर्भरता कम करने के लिए स्वदेशी रक्षा निर्माण को बढ़ावा दिया।



**चीन और पाकिस्तान पर रुख बदलना:** मोदी की विदेश नीति चीन और पाकिस्तान के प्रति सख्त है। मोदी के प्रशासन ने चीन-भारत सीमा तनाव, खासकर 2020 के गलवान घाटी संघर्ष पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। 2019 में पुलवामा हमले जैसे आतंकी हमलों के बाद, वह पाकिस्तान के साथ अधिक आक्रामक रहे हैं, आतंकवाद विरोधी और अंतरराष्ट्रीय अलगाव पर ध्यान केंद्रित किया है। मोदी ने चर्चा के बजाय सैन्य निरोध और कूटनीतिक दबाव का इस्तेमाल किया है।

**भारतीय प्रवासियों तक पहुंच:** मोदी ने दुनिया भर में भारतीय प्रवासियों को शामिल करने को प्राथमिकता दी है। बड़ी भारतीय आबादी वाले देशों की उनकी लगातार यात्राएं, साथ ही "प्रवासी भारतीय दिवस" ने विदेश में रहने वाले भारतीयों के साथ संबंध स्थापित करने और भारत की समृद्धि के लिए आर्थिक और सांस्कृतिक समर्थन आकर्षित करने का प्रयास किया।

**वैश्विक शासन में भारत की भूमिका का विस्तार:** भारत ने मोदी के तहत परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG), वासेनार व्यवस्था और मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था में सदस्यता के लिए आक्रामक रूप से प्रयास किया है। मोदी का प्रशासन जलवायु चर्चाओं में सतत विकास के लिए भारत की प्रतिबद्धता दिखाने के लिए अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का सह-नेतृत्व करता है।

**डिजिटल कूटनीति और सांस्कृतिक विरासत का लाभ उठाना:** मोदी की विदेश नीति डिजिटल प्लेटफॉर्म और यूनियन दिवस योजना जैसी रचनात्मक पहलों का उपयोग करती है, ताकि भारत के विश्वव्यापी प्रभाव का विस्तार किया जा सके। यह रणनीति भारत के सांस्कृतिक इतिहास का उपयोग सॉफ्ट पावर के रूप में करती है, ताकि वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बना सके। मोदी ने एक साहसिक, अधिक आक्रामक विदेश नीति बनाए रखी है, जो रणनीतिक स्वायत्तता और बहुध्रुवीय दुनिया को प्राथमिकता देती है। क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक लचीलापन और हार्ड और सॉफ्ट पावर के बीच संतुलन भारत को एक विश्वव्यापी शक्ति बनाने के उनके लक्ष्य रहे हैं।

डॉ. मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी की विदेश नीति के दृष्टिकोण अलग-अलग हैं, हालांकि दोनों ही भारत के कूटनीतिक सिद्धांतों पर आधारित हैं। सिंह ने स्थायी संबंध और आर्थिक सहयोग बनाने के लिए आर्थिक कूटनीति, बहुपक्षवाद और जुड़ाव को प्राथमिकता दी। मोदी ने सिंह के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है, लेकिन भारत की सुरक्षा और स्वायत्तता पर जोर दिया है, जिससे एक अधिक मजबूत स्थिति दिखाई देती है। दोनों राष्ट्रपतियों ने भारत को एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने की कोशिश की है, लेकिन सिंह ने कूटनीति और वाणिज्यिक गठबंधनों का इस्तेमाल किया, जबकि मोदी ने सुरक्षा को प्राथमिकता दी है।

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में वैश्विक दिग्गजों, खास तौर पर अमेरिका और रूस के साथ भारत के संबंधों में बदलाव आया, जो वैश्विक रुझानों और भारत की बदलती विदेश नीति के लक्ष्यों को दर्शाता है।

2008 का अमेरिका-भारत असैन्य परमाणु समझौता डॉ. मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भारत-अमेरिका संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। इस महत्वपूर्ण समझौते ने भारत को एनपीटी से बाहर एक जिम्मेदार परमाणु राज्य के रूप में स्थापित किया और असैन्य परमाणु वाणिज्य को खोला, जिससे विश्वास और सहयोग बढ़ा। सिंह के प्रशासन ने आर्थिक और तकनीकी सहयोग को प्राथमिकता दी, जिससे अमेरिका एक महत्वपूर्ण विकास भागीदार बन गया। मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच रक्षा, तकनीकी और आतंकवाद विरोधी रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा दिया। मोदी ने उच्च स्तरीय बैठकें कीं, प्रमुख आर्थिक सौदों पर हस्ताक्षर किए और इंडो-पैसिफिक रणनीति में अमेरिका,

जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता (क्वाड) में भाग लिया। मोदी ने लोकतांत्रिक आदर्शों और सुरक्षा चिंताओं, खास तौर पर चीन के क्षेत्रीय प्रभाव के आधार पर भारत-अमेरिका संबंधों को अभूतपूर्व स्तर के सहयोग तक पहुंचाया है।

भारत और रूस के बीच संबंधों की विशेषता दशकों से रक्षा और रणनीतिक संरक्षण है। सिंह ने रूस के साथ भारत के पारंपरिक संबंधों को प्राथमिकता दी, अपने अधिकांश सैन्य उपकरण मास्को से खरीदे जबकि "बहु-संरक्षण" रणनीति को बनाए रखा। सिंह के प्रशासन ने भारत-अमेरिका संबंधों में सुधार के साथ कूटनीतिक रूप से संतुलन बनाने की कोशिश की। अमेरिकी आपत्तियों के बावजूद, मोदी की सरकार ने भारत-रूस संबंधों को महत्व दिया, जैसा कि एस-400 मिसाइल सिस्टम खरीद से पता चलता है। हालांकि, अमेरिका के साथ भारत के संबंध बढ़े और 2014 में क्रीमिया पर कब्जा करने और उसके बाद यूक्रेन में गतिविधियों के साथ रूस की दुनिया भर में स्थिति बदल गई, जिससे भू-राजनीतिक पृष्ठभूमि जटिल हो गई। जबकि मोदी ने रूस के संबंध को बनाए रखने की कोशिश की है, यह कठिन रहा है क्योंकि भारत मास्को के साथ अपने रक्षा और ऊर्जा संबंधों को खतरे में डाले बिना अमेरिका के साथ अधिक संरक्षण चाहता है

## वैश्विक शांति और परमाणु निरस्त्रीकरण नीतियों का अवलोकन

डॉ. मनमोहन सिंह (2004-2014) के प्रशासन ने वैश्विक शांति के लिए सतर्क, संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हुए परमाणु अप्रसार और निरस्त्रीकरण पर भारत की दीर्घकालिक स्थिति को प्राथमिकता दी। अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में भारत की दीर्घकालिक निरस्त्रीकरण स्थिति को दोहराते हुए, सिंह की नीतियों ने परमाणु मुक्त दुनिया के लक्ष्यों को बढ़ावा देना जारी रखा। विशेष रूप से चीन और पाकिस्तान के साथ क्षेत्रीय मुद्दों के संदर्भ में, उनकी सरकार ने अक्सर कूटनीति-आधारित संघर्ष समाधान की वकालत की और सैन्यीकरण पर बातचीत का आग्रह किया। वैश्विक शांति को बढ़ावा देने की उनकी रणनीति में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय गठबंधनों को मजबूत करना भी शामिल था, जैसे कि अमेरिका और जापान के साथ, ताकि परमाणु हथियारों के प्रसार के खिलाफ एक एकीकृत रुख अपनाया जा सके।

विश्व शांति लाने के लिए, नरेंद्र मोदी के प्रशासन ने 2014 में पदभार ग्रहण करने के बाद से एक अधिक सशक्त और सक्रिय विदेश नीति को प्राथमिकता दी है, जिसे "शक्तिशाली कूटनीति" भी कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इज़राइल जैसे देशों के साथ रक्षा संबंधों को मजबूत करने के अलावा, मोदी के प्रशासन ने चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता (क्वाड) जैसे महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय मंचों में भारत की भागीदारी का विस्तार किया है। भले ही मोदी परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया के पक्ष में हैं, लेकिन उनके प्रशासन ने एक जटिल, बहुध्रुवीय दुनिया में भारत की सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने पर अधिक ध्यान दिया है। भारत ने मोदी के नेतृत्व में अपनी सीमाओं की रक्षा करने और आस-पास के देशों से संभावित खतरों को हतोत्साहित करने के लिए एक मजबूत रुख अपनाया है, खासकर इंडो-पैसिफिक में चीन की शक्तिपूर्ण कार्रवाइयों के मद्देनजर।

## परमाणु निरस्त्रीकरण और अंतरराष्ट्रीय संधियाँ

डॉ. सिंह अंतरराष्ट्रीय परमाणु निरस्त्रीकरण के अपने समर्थन में दृढ़ रहे। हालाँकि, उन्होंने व्यापक परमाणु-परीक्षण-प्रतिबंध संधि (CTBT) और परमाणु हथियारों के अप्रसार पर संधि (NPT) का विरोध किया क्योंकि भारत का मानना था कि वे भेदभावपूर्ण थे। इसके बजाय, सिंह की सरकार ने सार्वभौमिक निरस्त्रीकरण को बढ़ावा दिया, किसी भी एक राष्ट्र पर प्रतिबंधों से मुक्त वैश्विक ढांचे का प्रस्ताव रखा। उन्होंने 2008 में अमेरिका-भारत असैन्य परमाणु समझौते पर

हस्ताक्षर किए, जिसने अपनी रणनीतिक स्वायत्तता का त्याग किए बिना अप्रसार के लिए समर्पित एक जिम्मेदार परमाणु राज्य के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत किया और असैन्य परमाणु व्यापार की अनुमति दी।

एनपीटी और सीटीबीटी के भेदभावपूर्ण चरित्र के बारे में इसी तरह की चिंताओं को दोहराते हुए, मोदी सरकार ने मुख्य रूप से उनमें शामिल होने के खिलाफ भारत की स्थिति को बरकरार रखा है। परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) में प्रवेश के लिए आक्रामक रूप से प्रयास करके, जो भारत को महत्वपूर्ण परमाणु प्रौद्योगिकी प्राप्त करने और अपने नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की अनुमति देगा, उनकी सरकार ने भारत को एक जिम्मेदार परमाणु राज्य के रूप में स्थापित करने की कोशिश की है। भले ही "नो फर्स्ट यूज" दर्शन कभी-कभी आंतरिक विवाद का केंद्र रहा हो, मोदी सरकार ने भारत की गैर-आक्रामक परमाणु रणनीति को रेखांकित करने के लिए कार्रवाई की है।

## परमाणु नीति और रणनीतिक साझेदारियां

सिंह प्रशासन की परमाणु नीति पड़ोसी और दूर के देशों दोनों के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाने पर केंद्रित थी। अमेरिका के साथ 2008 का परमाणु समझौता सिंह की परमाणु नीति की आधारशिला थी, जिसने भारत को शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु तकनीक तक पहुंच प्रदान की और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भारत की स्थिति को बढ़ाया। सिंह की नीति में सॉफ्ट पावर और रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें अक्सर परमाणु प्रसार के खिलाफ चिंताओं को व्यक्त करने और शांति की वकालत करने के लिए संयुक्त राष्ट्र जैसे बहुपक्षीय मंचों का सहारा लिया जाता था।

मोदी के नेतृत्व में भारत की परमाणु नीति उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति का अभिन्न अंग बन गई है। मोदी ने अमेरिका, जापान और फ्रांस जैसे परमाणु-सक्षम देशों के साथ संबंधों को मजबूत किया है, तथा एनएसजी और वासेनार व्यवस्था जैसे प्रमुख परमाणु और रणनीतिक समूहों में भारत के प्रवेश की वकालत की है। उनके प्रशासन ने घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए "मेक इन इंडिया" जैसी पहल भी की है, जिसमें परमाणु प्रौद्योगिकी में प्रगति शामिल है। मोदी ने सतत विकास के लिए भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र के निर्माण पर जोर दिया है, जिसका उद्देश्य जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करना और जलवायु परिवर्तन को संबोधित करना है।

## क्षेत्रीय स्थिरता और परमाणु पड़ोसियों के साथ संबंध

सिंह ने पाकिस्तान और चीन जैसे परमाणु संपन्न पड़ोसियों के साथ संतुलित कूटनीति की नीति अपनाई, जिसका उद्देश्य तनाव को बढ़ाए बिना उसे कम करना था। उनके प्रशासन ने पाकिस्तान के साथ बातचीत की और बैकचैनल कूटनीति के माध्यम से कश्मीर संघर्ष और परमाणु हथियार नियंत्रण जैसे विवादास्पद मुद्दों पर आम सहमति बनाने का लक्ष्य रखा। चीन के साथ, सिंह की सरकार ने सीमा मुद्दों को सावधानीपूर्वक संबोधित करते हुए आर्थिक सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया। सिंह का दृष्टिकोण टकराव के बजाय जुड़ाव के माध्यम से क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने की ओर झुका।

मोदी सरकार ने पाकिस्तान और चीन दोनों के प्रति कड़ा रुख अपनाया है। उनकी नीति भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए कूटनीतिक, आर्थिक और, जहाँ आवश्यक हो, सैन्य उपाय अपनाने की इच्छा से चिह्नित है। क्षेत्रीय चुनौतियों के प्रति मोदी की प्रतिक्रिया में चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर सैन्य रुख बढ़ाना और सीमा पार आतंकवाद की घटनाओं के बाद अंतरराष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को अलग-थलग करने के लिए कूटनीतिक अभियान शामिल है। क्षेत्रीय स्थिरता के संबंध में मोदी की परमाणु नीति आत्मरक्षा और "पहले इस्तेमाल न करने" की



नीति पर जोर देते हुए निवारण पर केंद्रित है, जबकि यह सुनिश्चित करते हुए कि भारत आक्रामकता का दृढ़ता से जवाब देगा।

## शांति और परमाणु नीति पर तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य

डॉ. मनमोहन सिंह की विदेश नीति ने भारत की शांति की स्थापित परंपरा का काफी हद तक पालन किया, जिसमें बहुपक्षीय दृष्टिकोण के माध्यम से परमाणु निरस्त्रीकरण की वकालत की गई और शांतिप्रिय राष्ट्र के रूप में भारत की भूमिका को मजबूत किया गया। उनके प्रशासन ने कूटनीतिक समाधानों पर जोर दिया, परमाणु और गैर-परमाणु राज्यों के साथ स्थिरता और आर्थिक सहयोग को प्राथमिकता दी इसके विपरीत, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का दृष्टिकोण एक अधिक मुखर रुख को दर्शाता है, जो कूटनीति और मजबूत रक्षा उपायों के व्यावहारिक मिश्रण द्वारा चिह्नित है। उनकी नीतियां आत्मनिर्भरता, सुरक्षा और रणनीतिक साझेदारी पर जोर देती हैं, जो भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव का लाभ उठाकर ताकत की स्थिति से शांति की वकालत करती हैं हालांकि, दोनों नेता जिम्मेदार परमाणु नीति और परमाणु मुक्त दुनिया के बड़े लक्ष्य के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर एकमत हैं, हालांकि वे वैश्विक मंच पर इन उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के अपने तरीकों में भिन्न हैं। यह तुलनात्मक विश्लेषण इन दोनों प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में शांति और परमाणु मुद्दों पर भारत की विदेश नीति के विकास पर अधिक विस्तृत शोध पत्र के लिए आधार के रूप में काम कर सकता है।

## निष्कर्ष

डॉ. मनमोहन सिंह और नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व के तहत 2009 से 2024 तक भारत के आर्थिक प्रदर्शन का यह तुलनात्मक आकलन जीडीपी विकास के आंकड़ों और वास्तविक समय के आर्थिक संकेतकों के बीच काफी अंतर दिखाता है। जीडीपी विकास का उपयोग ऐतिहासिक रूप से आर्थिक गतिविधि का अनुमान लगाने के लिए किया जाता रहा है, लेकिन अध्ययन में असंगतताएं पाई गईं, जो क्षेत्र-विशिष्ट मैट्रिक्स के साथ व्यापक आर्थिक आंकड़ों को पूरक करने की आवश्यकता को प्रदर्शित करती हैं। 2009 से 2014 तक, भारत मनमोहन सिंह के तहत सभी क्षेत्रों में विकसित हुआ। इस अवधि में वाहन बिक्री, कृषि मशीनरी, व्यक्तिगत ऋण और आयकर प्राप्तियों में मजबूत वृद्धि देखी गई। इन मैट्रिक्स ने मजबूत उपभोक्ता विश्वास, कृषि उत्पादन और वित्तीय क्षेत्र की वृद्धि को दिखाया, जिससे अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला। जबकि जीडीपी वृद्धि मजबूत थी जीडीपी वृद्धि अनुमानों और वास्तविक समय के आर्थिक संकेतकों के बीच का अंतर यह दर्शाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था का आकलन करना कितना मुश्किल है। दोनों सरकारों ने विकास को बढ़ावा दिया, लेकिन क्षेत्रीय प्रदर्शन से पता चलता है कि नीतिगत निर्णय व्यक्तिगत उद्योगों और उपभोक्ता आदतों को कैसे प्रभावित करते हैं। नीति निर्माताओं को एक संतुलित रणनीति का उपयोग करना चाहिए जो वास्तविक समय के क्षेत्र के आंकड़ों के साथ व्यापक आर्थिक संकेतकों को जोड़ती है।

## संदर्भ

1. बनर्जी, ए., और डुफ्लो, ई. (2014) भारत का आर्थिक सर्वेक्षण: 2013-2014, नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
2. भल्ला, एस. (2024) नागरिक बनाम बाजार: कैसे नागरिक समाज संकट के समय में अर्थव्यवस्था पर पुनर्विचार कर रहा है, एमआईटी प्रेस।

3. भल्ला, एस. एस. (2017) राष्ट्रों की नई संपत्ति। नई दिल्ली: साइमन एंड शूस्टर इंडिया।
4. भंडारी, आर. (2020) भारत में वास्तविक समय के आर्थिक संकेतक और जीडीपी वृद्धि: एक तुलनात्मक विश्लेषण, जर्नल ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज, 41(2), 215-230। doi:10.1108/JES-12-2024-0403
5. चतुर्वेदी, एस., और पाठक, पी. (2016) नरेंद्र मोदी की विकास रणनीति: सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन के साथ मुलाकात, जर्नल ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, 18(2), 245-260.
6. डीटन, ए., और ड्रेज़, जे. (2002) भारत में गरीबी और असमानता: एक पुनर्मूल्यांकन. नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.
7. घाटे, सी., और राइट, एम. (2017) भारत में विकास के लिए आर्थिक संकेतक और उनके निहितार्थ. इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 52(30), 45-52. <https://www.epw.in> से लिया गया
8. झा, एस. (2017) जीडीपी वृद्धि पर पुनर्विचार: पद्धतिगत मुद्दे और चुनौतियाँ. इकोनॉमिक अफेयर्स, 67(3), 451-467. doi:10.5958/0976-4666.2017.00054.5
9. कुमार, एन., और मुंडले, एस. (2018) आर्थिक सुधार और आर्थिक प्रदर्शन: भारत का एक केस स्टडी. जर्नल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, 23(2) 189-216. doi:10.1007/s10887-018-9152-2
10. कुंडू, ए. (2015) आर्थिक सुधार और विकास: मनमोहन सिंह के सम्मान में निबंध. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.
11. पनगढ़िया, ए. (2013) भारत: उभरता हुआ दिग्गज. न्यूयॉर्क: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.
12. राजन, आर. (2024). जीडीपी वृद्धि और अनौपचारिक क्षेत्र: एक महत्वपूर्ण विश्लेषण. भारतीय आर्थिक समीक्षा, 56(4), 567583. doi:10.1177/0019466220912320
13. रंगराजन, सी., और श्रीवास्तव, डी. के. (2016) भारतीय अर्थव्यवस्था: नीतियां, प्रदर्शन और चुनौतियां. नई दिल्ली: अकादमिक फाउंडेशन.
14. राव, वी., और कुमार, ए. (2020) भारत की आर्थिक वृद्धि का आकलन: वास्तविक समय संकेतक बनाम जीडीपी आंकड़े। आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, 55(12), 25-31।